

इस काम के लिये पूर्ण सन्यावह (टोटल मोबिलिजेशन) किया तो मुझे पूर्ण आशा है कि हम देश के अन्दर ही काफी रुपया प्राप्त कर लेंगे।

इसके साथ ही साथ हमारे देश में जो बड़े जमींदार और राजा महाराजा हैं उनके पास अब भी काफी रुपया पड़ा है। बहुत सा ज़ेवर उनका छिपा पड़ा हुआ है, उनके नुमाइन्दे यहां पर बैठे हुये हैं, फारेन इन्वेस्टमेंट को कंफिस्केट कर लेना चाहिये। उद्योगपतियों के जो कल कारखाने हैं उन्हें सरकार नेशनलाइज कर ले और जो उचित मुआवज़ा है वह दे दे। देश में इस समय सरकारी कर्मचारियों की कमी है। जो राष्ट्रीयकरण द्वारा कल कारखानों को चला सकें इसलिये इन कल कारखानों को सरकार अपने कब्जे में जब कर लेगी तो इतने मालदारों और उद्योगपतियों को ही उन कारखानों के जनरल मैनेजर के रूप में रख सकती है और दो चार हजार रुपया तनख्वाह भी दे सकती है। इसी तरह से योजना को पूरा करने के लिये, देश की भलाई के लिये हमें जितनी भी दिक्कतों का सामना करना पड़े, सब को, चाहे वह किसान हो, विद्यार्थी हो, नौजवान हो, गरीब हो, अमीर हो, टोटल मोबिलिजेशन करके, समान रूप से सामना करना चाहिये ताकि हमारी द्वितीय योजना पूरी हो सके। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस रूप में हमारा यह काम अभी चल रहा है उससे हमारी योजना पूरी नहीं हो सकती है। इसमें कमी जो है वह जनता के सहयोग की कमी है। बगैर जनता को साथ लिये हुये हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। जनता को साथ लेना ही नहीं है, उसमें उत्साह भी पैदा करना है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव की तहदिल से तार्हद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे प्लानिंग मिनिस्टर महोदय इस प्रस्ताव को अवश्य स्वीकार करेंगे।

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT (EXCLUDING RAILWAYS) IN THE YEAR 1957-58

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI T. T. KRISHNAMACHARI) : Mr. Deputy Chairman, I beg to lay on the Table a statement showing the Supplementary Demands for Grants for Expenditure of the Central Government (excluding Railways) in the year 1957-58. [Placed in Library. See No. LT-425/57.]

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

THE COAL BEARING AREAS (ACQUISITION AND DEVELOPMENT) AMENDMENT BILL, 1957

SECRETARY: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary of the Lok Sabha:—

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith a copy of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Amendment Bill, 1957, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 5th December, 1957."

I lay the Bill on the Table.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at half-past two of the clock, THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. B. JOSHI) in the Chair.

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTION REGARDING MOBILISING PUBLIC ENTHUSIASM AND SUPPORT FOR THE SECOND FIVE YEAR PLAN— continued

श्री देवकीनन्दन नारायण (मुम्बई) :
भादरणीय उपसभाध्यक्ष जी, इस प्रस्ताव के

[श्री देवकीनन्दन नारायण]

उद्देश्य को देखते हुये मेरे खयाल से इसकी कोई मुखालफत नहीं कर सकता क्योंकि इसका उद्देश्य साफ है कि प्लान को कामयाब करने के लिए जनता का अधिक से अधिक कोआपरेशन पैदा करना चाहिये और जिस जनता को सोशल वेलफेयर प्रोग्राम से यानी सामूहिक विकास में लाभ होगा, उस जनता को प्रथम जायत करना चाहिये। तो इस उद्देश्य से कौन मुखालफत कर सकता है। परन्तु मेरे भाई अलगू राय शास्त्री जी ने सुबह किस बिना पर मुखालफत की, मैं तो नहीं समझ सका। मैंने समझने की कोशिश भी की, पर कुछ नहीं समझा। आखिर कोई यह तो नहीं कहता कि सरकार अपनी ओर से कोशिश नहीं कर रही है। काफ़ी कोशिश हो रही है, कामयाबी भी काफ़ी हुई है, परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि बहुत कुछ करना बाकी नहीं है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है और जो कुछ बाकी है, यदि उसको कामयाब करना है तो जनता के कोआपरेशन की आवश्यकता है और इस प्रस्ताव में यह बात साफ़ कहो गई है कि जनता का मैक्सिमम कोआपरेशन पैदा करना चाहिये।

हमें यह देखना चाहिये कि आज प्लान की जिन चीज़ों का सम्बन्ध जनता से है, उन कामों में जनता का कोआपरेशन प्राप्त हो रहा है या नहीं। बड़े बड़े कारखाने खुल रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं, रेलें बन रही हैं, लोहे के कारखाने खुल रहे हैं, ये सब ठीक हैं। मैं यह नहीं कहता कि यह नहीं हो रहा है, परन्तु जिन बातों से जनता का सम्बन्ध है, वहाँ पर हमें देखना चाहिये कि जनता का हमें पूरी तरह से कोआपरेशन मिल रहा है या नहीं। जहाँ तक मैं देखता हूँ, हमारे प्लान की आत्मा कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स और गैंगल विकास प्रोग्राम्स हैं। यह जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है, यह खासकर इस प्लान का आत्मा है। तो ये दो बातें ऐसी हैं जिनका सम्बन्ध पाँच लाख गांवों में बसे हुये ८० करोड़ हिन्दुस्तानियों से है। ठीक ही हमारे

नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि जब तक यामों का सुधार नहीं होगा तब तक हिन्दुस्तान का विकास हो रहा है, यह कहना मुश्किल है। इस निगाह से आप देखेंगे तो कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स का सबसे पहले गांवों से सम्बन्ध आता है और इन कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में देखिये कि क्या हो रहा है। हर एक प्रान्त का तजुर्बा अलग अलग हो सकता है। मेरा भी कुछ तजुर्बा है। मैं देखता हूँ कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स का जो काम चल रहा है वह सरकारी अफसरों की मार्फत चल रहा है और जितना कोआपरेशन जनता का मिलना चाहिये या पैदा होना चाहिये वह न मिल रहा है और न पैदा हो रहा है। मेरी यह शिकायत है कि खास कर कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में जो आफिसर हैं—खासकर मैं अपने प्रान्त का तजुर्बा बयान करता हूँ—वे आम जनता और सरकार जो वालंटरी कार्यकर्ता हैं उनका कोआपरेशन लेने की कोई खास कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है। असल में उनका कोआपरेशन नहीं चाहते और जो उनके हाँ नीचे नीचे लोग हैं उनसे वे काम करवाया करते हैं। हमें कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स की ओर देखते वक्त यह देखना चाहिये कि जहाँ पर कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स का काम हो रहा है वहाँ किस तरह की बेहतरी हो रही है। क्या वहाँ माली हालत सुधर रही है, क्या खेती की पैदावार वहाँ बढ़ रही है, क्या वहाँ ग्रामोद्योग बढ़ रहे हैं, क्या वहाँ घरों की कोई दुश्स्ती हो रही है, क्या वहाँ रूरल हाउसिंग में कोई सुधार हो रहा है, जब इस तरह की चीज़ें आप देखें तो आपको कहना होगा कि अभी दिल्ली बहुत दूर है।

प्लान का असली मकसद जो है वह यह है कि असम जनता को उससे लाभ पहुंचना चाहिये। मैं तो यह नाप हाथ में रखता हूँ कि जो आखिरी मनुष्य है, लास्टमैन अनि दी लास्ट लैडर है, उसकी हालत किस तरह से सुधर रही है, उसका कितना कोआप-

रेशन मिल रहा है और वह इसमें कितनी मदद देने के लिए तैयार है। मुझे आश्चर्य होता है जब कभी मैं यह सुनता हूँ कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स से एक रेबोल्यूशन हिन्दुस्तान में हो रहा है, एक काया कल्प हो रहा है। मुझे तो कहीं काया कल्प दिखाई नहीं देता और न कहीं रेबोल्यूशन दिखाई देता है। माफ कीजियेगा, शायद मैं ऐसे शब्द कहते वक्त कुछ बड़े लोगों से अलग राय व्यक्त कर रहा हूँ, परन्तु यह बात बिल्कुल सत्य है। आप मेरे साथ चलिए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ और देखना चाहता हूँ कि कहां पर, किस प्रान्त में कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स की वजह से रेबोल्यूशन या काया कल्प हो रहा है। काया कल्प हो यह हम भी चाहते हैं, परन्तु काया कल्प तो तब होगा जब आम जनता के विचारों में, आम जनता के प्रयत्नों में एक बनियादी तन्बोली हो जायगी और आम जनता इस कार्य को अपना समझ कर करने लगेगी। एबोल्यूशन कमेटी जो बलवन्तराय मेहता जी की अध्यक्षता में स्थापित हुई थी, उसकी रिपोर्ट आपने देखी होगी। उन्होंने भी यह शिकायत की है कि इस काम में राज्य सरकारों को जितना सहयोग देना चाहिये और जितनी उनको दिलचस्पी लेनी चाहिये, उतना न वे सहयोग दे रही हैं और न दिलचस्पी ले रही हैं। जब उनकी शिकायत यहां तक है कि राज्य सरकारें दिलचस्पी नहीं ले रही हैं, तो आम जनता के सम्बन्ध में हम क्या खयाल कर सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि एक बजट पांच सात लाख का होता है जो ऊपर से बनाया जाता है और नीचे नाम के लिए पूछा जाता है। उसमें कहां तक सहयोग लोगों का रहता है यह आप सब लोग जानते हैं। इसी लिए उन्होंने यह बात कही है कि यह सहयोग पैदा करने के लिये बहुत कुछ काम पंचायतों में सुपुर्द करना चाहिये। यह बात जरूर है कि हमारे यहां प्रोजेक्ट एरियाज में सड़कें और रास्ते बन रहे हैं, स्कूल दुस्त हो रहे हैं, कुछ पंचायतों के मकान बन गये हैं, कुछ सामाजिक

शिक्षा का भी प्रयोग हो रहा है, परन्तु गांवों को आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह विकसित करने के लिये कोई टार्गेट्स बनाये गये हों और उन टार्गेट्स तक पहुंचने के लिए लोगों का प्रयत्न हो रहा हो, ऐसी बात कहीं दिखाई नहीं देती। यह तो तब दिखाई देगी जब लोगों का पूरा कोआपरेशन आप को मिल जायगा।

जहां तक सोशल वेलफेयर की बात है, सोशल वेलफेयर के बारे में जितना थोड़ा कहा जाय, उतना ही सत्य है। इसमें विशेष यह बात है कि सोशल वेलफेयर का सारा काम बहनों को सौंपा गया है। यहां बहनों दिखाई नहीं दे रही हैं, एक या दो बहनें ही इस वक्त यहां पर हैं, परन्तु मैं खास कर मिनिस्टर साहब के कानों तक यह बात पहुंचाना चाहता हूँ कि यह सोशल वेलफेयर का काम जिन बहनों को सौंपा गया है, वे अधिकतर बलब लेडीज हैं, फेशनबिल लेडीज हैं, और यह काम उनके सुपुर्द होने के बाद शायद वे कभी देहात में पहुंचेंगी और खेत देखें हों, लेकिन इससे पहले उन्होंने कभी खेत देखे हों, ऐसा मैं नहीं समझता। (Interruptions.) इस लिए जब आप देहातों का सुघार करना चाहते हैं, देहात की बहनों को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो आप ऐसी बहनों के जिम्मे यह काम करिये जिन को गांवों की बहनों से आत्मीयता है। जिन बहनों में आत्मीयता नहीं होगी, जिनमें एक तरह का ममत्व नहीं होगा, वे इस काम को ठीक नहीं कर पायेंगी।

श्री मेनिश्वरराय गुप्त (नाम निर्दिशित) : सावित्री जी से अपील कीजिये।

श्री देवकीनन्दन नारायण : जब गांव की बहनें इन पड़ी लिम्बो और फेशनबिल बहनों को देखती हैं तो वे सकुचा जाती हैं और उनके पास जाना तक नहीं चाहतीं, यह मेरा सजुर्बा है और यह मैंने देखा है। इस लिए मैं खास कर यह कहना चाहता हूँ कि

[श्री देवकीनन्दन नारायण]

सोशल वेलफेयर काम को आप ऐसी बहनों के सुपुर्द कीजिये जिन्होंने इस काम के लिए अपना समय और अपना जीवन कम या अधिक अर्पण किया हो सोशल वेलफेयर के बारे में मुझे एक बात और कहनी है। आपने तमाम जीपें अधिकारियों को दे रखी हैं, आप ज़रा तलाश कीजिये कि इन जीपों का क्या होता है, इन जीपों में कौन दौड़ते हैं, कौन प्रवास करता है और कितनी उनकी माइलेज होती है। ये तमाम बात आप देखेंगे तो आपको बता चलेगा कि सोशल वेलफेयर के नाम से बहुत कुछ जो काम हो रहा है, वह खास कर देहातों में नाममात्र का ही हो रहा है।

श्री शीलनद्र याजी : अभी शुरूआत है।

श्री देवकीनन्दन नारायण : इसके बाद सोशल वेलफेयर . . .

(Interruption.)

This is not unfair. This is a statement of fact. I told him just now. मैंने यह कहा कि हिन्दुस्तान में ऐसी बहनें मौजूद हैं जो इस काम को कर सकती हैं और वे योग्य हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हिन्दुस्तान में योग्य बहनें नहीं हैं, परन्तु शहरों की बहनों, खास कर क्लब लेडीज़ को ऐसे काम सुपुर्द नहीं करने चाहियें, जिनका कि आज तक देहातियों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहा और न उनके साथ आत्मीयता का भाव पैदा हुआ हो।

इसके बाद खेती के बारे में हमें कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स एरियाज़ की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये जिससे उत्पादन बढ़े। परन्तु हिन्दुस्तान की खेती को देखते हुए, यह बात माननी पड़ती है कि सिर्फ खेती का उत्पादन बढ़ाने से ही काम नहीं चलगा, उसकी भी मर्यादा है कि कहां तक बढ़ सकती है। हमारे गांवों के किसानों को बड़ी मुश्किल से खेती में पांच छः महीने काम मिलता है

और बाकी पांच, छः महीने बेकार रहते हैं इस लिये जब तक आप ग्रामोद्योगों का आश्रय नहीं लेंगे तब तक आप पूरी तरह से खाली वक्त में उनको उद्योग नहीं दे सकेंगे, न ग्रामों का भला ही कर सकेंगे। बहुत दिनों तक—मेरे ख्याल से पहले दो वर्षों तक—ग्रामोद्योग का काम कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स के कामों में शामिल तक नहीं था। मेरे इस कथन में यदि गलती हो तो मिनिस्टर साहब दुरस्त कर सकते हैं। शायद दस वर्ष से पहले वर्ष मसूरी में या वहीं ओर कॉफरेंस हुई थी, वहां प्रथम यह उपाय सोचा गया कि ग्रामोद्योग को भी खास स्थान दिया जाना चाहिये और कुछ ऐसे क्षेत्र—जैसे इंटेंसिव एरियाज़ के नाम से पुकारा जाता है—कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स में रखे जाने चाहिये कि जहां ग्रामोद्योग को प्रधानता दी जाय। मेरा कहना यह है कि जब आप गांवों की, देहातों की, बात करते हैं तब आप को ग्रामोद्योगों का विकास करना चाहिये क्योंकि उनको बढ़ाने से और अधिक उत्पादन से ही हमारे किसानों की मदद हो सकती है।

आपने देखा होगा, अभी अभी अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने आई है, उस रिपोर्ट में हमारी अन्न की कमी की चर्चा करते हुये एक खास बात की ओर ध्यान दिलाया गया है। उसमें दो बातें कही गई हैं लेकिन मैं एक बात की ओर आप का ध्यान खींचना चाहता हूँ और वह है फ़ेमिली प्लानिंग। इस रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि उत्पादन जितना बढ़ता है उतना खर्च हो जाना है क्योंकि उत्पादन जितना होता है उतने ही खाने वालों के मुँह बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ खाने वाले तो बढ़ते जा रहे हैं परन्तु दूसरी तरफ उत्पादन कहां तक बढ़ सकता है इस लिये जब तक आप खाने वालों की पैदाइश को मर्यादा में नहीं लायेंगे तब तक अन्न की कमी जारी रहेगी। इसलिये प्लानिंग कमीशन को इस चीज का खास कर देहातों में प्रचार करना चाहिये क्योंकि उन बेचारों में आज अज्ञान है . . .

(Time bell rings.)

I shall finish within five minute:.,

MR. VICE-CHAIRMAN (SHRI M. B. JOSHI):
Not five minutes.

SHRI DEOKINANDAN NARAYAN:
I did not know about it otherwise I
would have been shorter.

तो ज्यादा से ज्यादा जोर ग्रामों में देना चाहिये, शहरों में फ्रेमिली प्लानिंग पर आप ज्यादा जोर क्यों देते हैं? एक वक्ता मेने कहा था कि भागवानों को तो लड़के लड़कियां होने नहीं हैं, अधिकतर गरीबों के घर में दिखाई देती है। यदि फ्रेमिली प्लानिंग की जरूरत है तो गांवों में है।

आप स्माल मेविंग्स की बात करते हैं। स्माल सेविंग्स आपको बहुत मिल सकती है, परन्तु उसको एकत्रित करने के लिये भी आपको कोआपरेशन की जरूरत है, देहातियों के कोआपरेशन की जरूरत है। अगर आप विद्यार्थियों में स्माल मेविंग्स का प्रचार करें, प्राथमिक स्कूल से लेकर कॉलेज के विद्यार्थियों तक में, तो मेरा विश्वास है कि कई करोड़ रुपया आप एकत्र कर सकते हैं। मेरे प्रान्त में एक जिन्ने में एक आना, दो आना एकत्र करके यह प्रयोग किया जा रहा है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप ऐसा प्रोग्राम निश्चित करें कि प्राथमिक स्कूल से लेकर कालिज तक के विद्यार्थी साल में एक सप्ताह में एक बार ऐसा दिन मनायें जिसमें वे कुछ बचत करें, और उसे एकत्र करें, जैसे कि सिनेमा की बचत, होटल में न जाने में बचत, ऐसी बहुत सी बचतें हैं जो वे कर सकते हैं। इस तरह से आप विद्यार्थियों का कोआपरेशन लीजियेगा।

इसके बाद, आपका जो प्रचार का कार्य है वह आप पार्लियामेंट के मेम्बरों से लीजिये, लोकल बाडीज, एसेम्बली के मेम्बरों से लीजिये उनके सुपुर्द यह काम आप करियेगा। आप यहां इस्तहार छपाते हैं, मासिक पत्रिकायें

छपाते हैं जो कि ढेरों में राज्य सरकारों के दफ्तरों में पड़े रहते हैं और वे किसानों तक पहुंचने ही नहीं हैं। तो प्रचार का काम इन भाइयों को मौपना चाहिये जो यहां बैठे हुए हैं। यदि आपको जनता का कोआपरेशन प्राप्त करना है तो वह काम आप जनता के नुमायंदों को मौप दीजिये। अफसरों के जरिये आप बहुत कुछ कोआपरेशन प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मैं नहीं मानता।

अब आखिरी एक बात और मुझे कहनी है। हमारे साथी भाई पारिख साहब बोम्बे के लिये खड़े हुये तो उन्होंने पहले प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की बात शुरू की और आखिर में यहां तक उतर आये और कहने लगे, हमारे मिनिस्टर्स तो लेमैन हैं। तो क्या मेरे भाई चाहते हैं कि उद्योगपति बना दिये जायें मिनिस्टर्स। हां, हो सकता है पैसा कमाने का काम हो तो मैं भी कह देता कि उद्योगपतियों को मिनिस्टर बना दिया जाय। परन्तु पैसा कमाना कुछ और होता है और राज चलाना और बात हुआ करती है, यह मेरे भाई को जानना चाहिये, और इस तरह से यह कहना कि हमारे मिनिस्टर्स लेमैन हैं यह उनको शोभा नहीं देता। (Time bell rings). पैसे की बदौलत सब काम नहीं हुआ करते हैं।

आखिर में मेरी यही प्रार्थना है कि अगर जनता में कोआपरेशन का भाव पैदा करना है तो जनता के ही नेताओं को, जनता के ही नुमाइन्दों को जनता के पास जाना होगा और जनता से सहकार मांगना होगा। तब ही उसका सहकार मिल सकता है। इसमें जितनी मदद सरकार कर सके, करे। सिर्फ सरकार के ओहदेदार कोआपरेशन प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा मेरा तर्जुमा है।

श्री पां० न० राजभोज (मुम्बई) :
उपसमाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव हाउस

[श्री पा० ना० राजमोज]

के सामने प्रस्तुत किया गया है, मेरे खयाल से उसकी कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं थी। लेकिन शासन द्वारा इस सम्बन्ध में किये जाने वाले कार्य के विरुद्ध जो आवाज विरोधी दल लगा रहा है वह सर्वथा वृथा है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना तीन भागों में विभाजित होती है। एक तो मेरे खयाल से मेजर प्रोजेक्ट्स अर्थात् बड़ी योजनायें हैं। दूसरे हैवी इंडस्ट्रीज अर्थात् भारी उद्योग और तीसरे कम्प्यूनिटी प्रोजेक्ट्स अर्थात् समाज विकास। मेरे खयाल से जो पहली दो बातें मैंने बताईं यानी मेजर प्रोजेक्ट्स और हैवी प्रोजेक्ट्स, उसके लिये विशेष रूप से शिक्षा पाये हुये यंत्र और तंत्र विचारदों की आवश्यकता होती है। जो तीसरा भाग है समाज विकास का, इसके बारे में हम लोगों को पब्लिक का ज्यादा से ज्यादा सहकार मिलने की बहुत आवश्यकता है और इसके लिये प्रचार होना चाहिये। गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उसको भी मालूम होना चाहिये कि यह जो पंचवर्षीय योजना है वह किस तरह से अमल में आनी चाहिये। योजना का काम चलाने के लिये इस समय हमें विदेशों से अनुभवी, प्रशिक्षित विचारदों की सहायता लेनी पड़ती है। जहां तक समाज विकास का सम्बन्ध है उसमें हमें केवल जनता का सहयोग, जनता की सहायता, जनता का श्रम चाहिये और उसके लिये हमें उनमें काम करने की लगन और उत्साह जाग्रत करने की आवश्यकता है। देश के ३८ करोड़ लोगों के ७६ करोड़ हाथों की श्रम शक्ति पर हमारा योजना की सफलता निर्भर है और सरकार इस ओर जितना ध्यान अब तक दे रही थी मैं समझता हूं कि उससे और अधिक ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। जिस दृष्टि से हम लोग चाहते हैं उस दृष्टि से सरकारी अधिकारी और जो जनता है, वह हमारी योजना के महत्व को देखना नहीं है। हम यहां कुछ बड़ी बड़ी बात करते हैं

लेकिन हमारे ५, ७ लाख देहातों की ग्रामीण जनता के उद्धार के लिये उनसे जितना श्रम लेना चाहिये उतना श्रम सरकार उनसे लेती नहीं है। हमारे मंत्री महोदय पब्लिक वर्कर हैं और वे समझते हैं कि उनका ज्यादा से ज्यादा विश्वास हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह काम केवल निःस्वार्थी समाज सेवकों द्वारा ही ठीक से हो सकता है जिनकी हमारे देश में कमी नहीं, परन्तु 'राइस सोलजर्स' पेट पालतू लोगों की फीज जमा करके यह काम नहीं हो सकता लेकिन उनमें से आदर्श सेवक और सेविका निर्माण करना चाहिये। तो यदि सरकार समाज सेवा संस्थाओं के जरिये से ज्यादा से ज्यादा सहकार लेना चाहें तो हम उनको देने के लिये तैयार हैं।

तीसरी बात जो मुझे कहनी है वह हरिजनोद्धार, शराबबन्दी, गंदी बस्तियां, समाज-कल्याण, आदिवासियों के कल्याण और ग्रामोद्धार आदि जो अनेक महत्वपूर्ण बातें हैं, उसके बारे में है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि इस कार्य को करने वाला जो अधिकारीवर्ग है वह इतना काम नहीं कर रहा है जितना कि उसे करना चाहिये। उसे अधिक ध्यान दे कर इस कार्य को करना चाहिये। अधिकारीवर्ग में से ऐसे अनेक लोग पाये जाते हैं जो केवल हरिजनों के हितों की उपेक्षा करते हैं और समय समय पर अपने कामों के द्वारा वे किसी हद तक अस्पृश्यता का पालन करते हैं, इसका परिचय देते हैं। श्री देवकीनन्दन नारायण जी ने समाज कल्याण बोर्ड के बारे में जो बातें कहीं उसके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि इस बोर्ड में इस समय ज़राया बहने ही काम कर रही है। इसमें फैंसनेबुल औरते ही ज्यादा है। मेरा तो यह खयाल है कि हरिजनोद्धार और समाज कल्याण बोर्ड में देहात के रहने वालों को काम करना चाहिये क्योंकि वे हैं उनके बारे में ज्यादा जानते हैं। इस समय इन संस्थाओं में बहुत अच्छे कार्यकर्त्ता हैं, लेकिन मैं बम्बई के बारे में बतलाना चाहता हूं कि बम्बई

के पूंजीवादी और बड़े अफसरों की औरतें, जिन्होंने कभी देहाती इलाका नहीं देखा है, समाजकल्याण बोर्ड में हैं। मुझे मालूम नहीं कि यह महिला जो कि मोटर में हर समय धूमती है देहात में क्या काम कर सकेगी। इस महिला को देहात के कण्टों के बारे में क्या मालूम होगा? इसलिये मेरा कहना है कि जो लोग समाज की उन्नति चाहते हैं, वे उनकी कठिनाइयों की भली भाँति समझते हैं उन्हें यह काम करने को देना चाहिये। हमारे हरिजन और आदिवासियों में बहुत सी बहनें हैं जो इस क्षेत्र में काम करना चाहती हैं और अच्छा काम कर सकती हैं। इसके विपरीत होता यह है कि महाराष्ट्र में समाज कल्याण बोर्ड में गुजरात का आदमी आना चाहता है। इस बेचारे को यह भी मालूम नहीं है कि कौन हरिजन है, कौन आदिवासी है। इस तरह का काम कुछ लोगों ने कभी भी नहीं किया है, फिर भी उन्हें यह काम सौंपा जा रहा है। मेरी प्रार्थना यह है कि इस कार्य में उन ही लोगों को लगाया जाना चाहिये जो कि इस काम में सम्बन्ध रखते हों। इसके साथ ही साथ में यह भी प्रार्थना करूँगा कि सरकार इन कार्यों के लिये ज्यादा धन खर्च दे ताकि यह काम अच्छी तरह से किया जा सके।

चौथी बात जो मुझे कहनी है वह ग्रामोद्योग के सम्बन्ध में है। इस योजना काल में यह कार्य किया जा रहा है जो योग्य है। मेरी प्रार्थना यह है कि जिनको सचमुच विकास और उन्नति की आवश्यकता है उनको इसमें स्थान नहीं दिया जाता है। इसके विपरीत यह हो रहा है कि ऐसे तत्वों को स्थान मिलता है जिन्हें उसकी जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल यह है कि ग्रामोद्योग का जो कार्य हो रहा है उसमें चर्म उद्योग को उचित स्थान नहीं मिल रहा है। आज करोड़ों रुपया सरकार चर्म उद्योग के बारे में खर्च कर रही है मगर देहातों में इस काम में लगे हुये लोगों को कोई उत्तेजना नहीं

मिलती है। हमारे मंत्री महोदय इस काम में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, मुझे आशा है कि वे उद्योग की कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करेंगे।

बहुत के दौरान साधु समाज के बारे में बात कही गई। मेरा अपना ख्याल यह है कि पुराने ख्याल के जो लोग हैं अगर वे किसी अच्छे काम में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो अच्छी बात है। इसी तरह से अगर साधु समाज भी सहयोग देना चाहता है तो इसमें अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन आप जानते हैं कि आज देश में जलसा करने वाले बहुत लोग हैं जो कि कोआपरेशन करने को तैयार हैं। आज हमारे देश में कई प्रकार की शक्तियाँ हैं जो कि राष्ट्रीय एकता बनाये रखने के लिये काम करने को तैयार हैं। इन सब को बढ़ावा मिलना चाहिये और हर तरह का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। मगर जिन संस्थाओं में जाति भेद की भावनाएँ अभी तक मौजूद हैं उन्हें इस तरह का प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये। अभी हाल में ग्रहमदाबाद में जो साधु समाज का सम्मेलन हुआ था उसमें साधु लोग हरिजनों के साथ बैठने को तैयार नहीं हुये। जब इन लोगों में इस तरह की मनोवृत्ति है तो यह किस तरह से देश का सुधार कर सकेंगे? जिन संस्थाओं में इस तरह की भावनाएँ अभी तक मौजूद हैं वे किसी तरह से भी जनता की भलाई नहीं कर सकते हैं और सरकार को भी उन्हें प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये।

अब मैं गंदी बस्तियों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ। आज हमारे देश में कई प्रकार की गंदी बस्तियाँ हैं और उनका सुधार करने के लिये कई प्रकार की शक्तियाँ कार्य कर रही हैं। लेकिन फिर भी देश में काफी गंदी बस्तियाँ पड़ी हैं जिन पर कई प्रकार से खर्च करने की आवश्यकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे नेता, हर वक्त बार बार कहते हैं

[श्री पा० ना० राजभोज]

कि ये गंदी बस्तियां हमारे देश के लिये एक कलंक हैं। जिस प्रकार हरिजनों के लिये अस्पृश्यता कलंक है उसी प्रकार देश के सामाजिक जीवन के लिये गंदी बस्तियों का नष्ट किया जाना आवश्यक है। मेरी इस सम्बन्ध में यह प्रार्थना है कि बम्बई पूना और दिल्ली तथा अन्य प्रांतों में जितनी भी गंदी बस्तियां हैं उन्हें हमें जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिये। हरिजनों और आदिवासीओं की जितनी भी गंदी बस्तियां इस समय देश में हैं वे जल्द से जल्द खत्म होनी चाहियें। मेरे पास इस समय इस सम्बन्ध में कहने के लिये ज्यादा समय नहीं है लेकिन मैं मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि देश के कार्यकर्ताओं और समाज सेवकों को अपने विश्वास में लेकर, देश में इस कार्य को करने के लिये जितने भी योग्य आदमी मिलते हैं, उनको साथ लेकर इस कार्य को कार्यान्वित करना चाहिये अंत में मैं फिर यह कहूंगा कि ग्रामोद्योग गंदी बस्तियों, समाज सुधार और नशाबंदी के सम्बन्ध में जो कुछ सुझाव दिये हैं उन्हें मंत्री महोदय अमल में लाने की कोशिश करेंगे।

श्रीमती सावित्री निगम (उत्तर प्रदेश) :
उपसभाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ा और पढ़ने के पश्चात् मुझे प्रतीत हुआ कि यदि इस प्रस्ताव को मूव करने वाले महोदय ने गवर्नमेंट स्पोक्समैन और देश के मौजूदा नेताओं के वक्ताओं को ध्यान से पढ़ा होता तो शायद वे कभी भी इस प्रस्ताव को मूव करने की आवश्यकता महसूस न करते।

श्रीमन्, पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में ही हमारे देश के कर्णधारों ने इस आवश्यकता को अलौभाति समझ लिया था और इसलिये उन्होंने भारत सेवक समाज जैसी एक विशाल संस्था का निर्माण किया, जिस का जर्म उद्देश्य लोगों से वालंटरी कोआपरेशन लेना

था। जन जन से सहकार लेना था और इस दृष्टि से जितनी भी योजनायें उसके क्षेत्र में संभव हो सकती थीं, बनाई गई थीं। इस प्रकार के देश के छोटे बड़े सभी शहरों में, गांवों में, जिलों में, भारत सेवक समाज की शाखायें खुल गईं। जिनके हृदय में देश प्रेम की आग थी, जिनके मन में देश सेवा के लिये विकलता थी, वे सभी लोग शामिल हो कर इसमें सहयोग दे रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह नहीं कि जितना वालंटरी कोआपरेशन हमें उन योजनाओं के लिये मिलना चाहिये था, वह सब हमें मिल चुका है और अब हम आगे प्रयत्नशील नहीं हैं। लेकिन जिस बात को आज हमारे चोटी के नेता बार बार खुले तौर पर दोहराते रहते हैं उसको प्रस्ताव के रूप में लाकर रखने में सदन का समय नष्ट करने के सिवाय कोई बात दिखाई नहीं देती है।

श्रीमन्, सोशल वेलफेयर बोर्ड के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। यह भी कहा गया है, कि सोशल वेलफेयर बोर्ड में फैशननेबल स्त्रियां काम करती हैं। मैं माननीय मेम्बर से पूछना चाहती हूं—स्त्रियों की बात तो जाने दीजिये कौन सा ऐसा आदमी है जो फैशन नहीं करता, तेल नहीं लगाता, मुंह में सफेदी नहीं लगाता और चमरीघ जूता नहीं पहिनता। मुझे ऐसा व्यक्ति बता दीजिये जो आजकल फैशन नहीं करता है? ऐसी स्त्रियों को जो कि कायदे में रहती हैं क्या उन्हें भगवान ने ऐसा बना कर आउट राइट कंडेम कर दिया है।

(Interruptions.)

3 P.M.

मैं यह विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहती हूं कि फैशननेबल स्त्रियों को बहुत बड़ा भवसर मिला है कि वे गांवों में जा कर लोगों की सेवा कर सकें और फिर जहां तक फैशननेबल स्त्रियों का सम्बन्ध है वे भी हमारे देश की बहनें हैं। कुछ माननीय सदस्यों

वे यह कहा कि वे काम नहीं करती हैं, मोटरों में चढ़ती हैं, परन्तु यदि वे पदा नहीं करती हैं और गांवों में लोगों की सेवा करने के लिये जाती हैं तो यह देश के लिये बड़ा शुभलक्षण है।

(Interruptions.)

मैं इस तरह के डिस्टर्बेंस को बिल्कुल परवाह करना नहीं चाहती। मैं बराबर अपनी बात कहती जाऊंगी।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. B. JOSHI) : No interruptions.

श्रीमती सावित्री लिगम : श्रीमान्, यह हम सभी चाहते हैं कि हमें गांव की बहनों और ग्रामीणों की मदद करनी चाहिये, लेकिन इस सम्बन्ध में मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहती हूं। यहां दिल्ली में एक सोशल वेलफेयर बोर्ड है और उसकी हालत पर जरा विचार कीजिये। भारत सेवक समाज ने यहां एक प्रोजेक्ट ले रखा है। हम लोगों ने पूरा प्रयत्न किया कि अगर हमें ग्रामीण बहनें मिल सकें, तो चाहे उनकी क्वालिफिकेशन कम हो क्यों न हो, फिर भी हम उनको रख लें, और शहर की एक बहन को भी हम वहां गांवों में न ले जाय, लेकिन आप विश्वास कीजिये कि तमाम प्रयत्न करने पर भी मुश्किल से १० प्रतिशत ऐसी बहनें मिल पायीं जां कि गांवों में काम कर सकती हों। हम ऐसी ग्रामीण स्त्रियों का भी स्वागत करने के लिये तैयार थे जिन की क्वालिफिकेशन भले ही कम हो, लेकिन फिर भी वे नहीं मिल सकीं। ऐसी दशा में कम से कम जिन स्त्रियों को क्लब लेडीज कहा गया, उनके हृदय में तो देश प्रेम जाग्रत हुआ और वे गांवों में जा कर सेवा करने के लिये प्रस्तुत हुई। एक भाई ने मुझ से पहले कहा कि ये बटरफ्लाइज क्या काम करेंगी। इसी लिये मैंने उनसे कहा कि आप बटरफ्लाइज

नहीं पसन्द करते हैं तो क्या कैंटरपिलर्स पसन्द करते हैं। तो बजाय इसके कि आप बटरफ्लाइज और कैंटरपिलर्स की बात पर जायें, आपको उनके सेवा के काम को देखना चाहिये। मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहती हूं कि वे चाहें जिस ढंग का कपड़ा पहनती हों, लेकिन उनकी सेवा भाव में कोई त्रुटि नहीं है और वे बहुत अच्छी तरह से सेवा का कार्य कर रही हैं। जहां तक यह प्रश्न है कि गांव की बहनों की उपेक्षा होती है, मैं चाहती हूं कि जो भी ऐसी गांव की बहनें हैं जो सेवा कर सकती हैं, उनका नाम और उनकी सूची सदस्य महोदय, दें। मैं उनको सूची मिसेज देशमुख के पास भेज दूंगी और मुझे आशा है कि वे उनकी पूरी मदद करेंगी, क्योंकि सोशल वेलफेयर बोर्ड का परम उद्देश्य ही यह है कि गांव गांव में एक नयी क्रांति का सृजन किया जाय जिससे एक एक झोंपड़ी के द्वार पर एक नयी क्रांति का आवाहन हो और एक एक झोंपड़ी में सेवक पहुंचें। भारतमाता ग्रामवासिनी है और जब तक यह नहीं होगा तब तक इस सोशल वेलफेयर बोर्ड का एक भी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

जहां तक सोशल वेलफेयर बोर्ड में परिवर्तन लाने का प्रश्न है कि गांव के लोगों को भी अवसर देना चाहिये, मैं संसद् सदस्यों से सर्वथा सहमत हूं कि वैसा ही होना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि एक रिजिड सा नियम बन जाय कि एक बार जो व्यक्ति सोशल वेलफेयर बोर्ड में आ गया वह सदा बना रहे। समाज में जो पढ़ी लिखी और योग्य बहनें हैं उनको भी काम करने का अवसर मिलना चाहिये।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात कहें बिना नहीं रह सकती कि जहां भी पब्लिक कोऑपरेशन की बात चलती है वहां एक सब से बड़ा प्रश्न जो पब्लिक कोऑपरेशन का है वह इग्नोर कर दिया जाता है। आप एक छोटी

[श्रीमती सावित्री निगम]

सी चीज देख लीजिए। यहां दिल्ली में एक प्रोहिबिशन बोर्ड था और उसके मातहत एक इम्प्लीमेंटिंग कमेटी बनी हुई थी। उसका काम मोहल्ले मोहल्ले में बोर्ड की शाखाएँ खोलना था और हर मोहल्ले में चार पांच आदमियों की कमेटी बना कर जो लोगों में सोशल सर्विस् होती थी या जो लोगों में शराब गांजा, चर्म आदि नशे पीने की आदतें होती थीं उन आदतों को समझा बजा कर छुड़ाना और हर तरह की सोशल और इकोनामिक मदद करना था। लेकिन जब दिल्ली स्टेट अमलगेमेट हुई और यूनियन टेरीटरी बनी तो ऐसा अच्छा काम करने वाला बोर्ड भी खत्म हो गया और फिर वह पुनर्जीवित नहीं किया गया। मैंने इसी सदन में जब प्रश्न किया कि वह बोर्ड क्यों नहीं पुनर्जीवित किया गया, तो यह उत्तर दिया गया कि सरकार उसकी आवश्यकता नहीं समझती। यह बड़ी खेदजनक बात है कि यह मानते हुये कि उस बोर्ड ने एक साल में इतना महत्वपूर्ण कार्य किया कि उसने मोहल्ले मोहल्ले में और गली गली में अपना प्रभाव फैला दिया और हजारों बिगड़े हुये घरों को सुधार दिया, फिर भी जनता का कोआपरेशन नहीं दिया जा सका। इस तरह सैकड़ों आदमियों का वालंटरी को-आपरेशन मिल रहा था, सैकड़ों कार्यकर्ता नशेबन्दी का काम निःशुल्क और बिना वेतन लिये करने के लिये तैयार हो गये थे, लेकिन उस बोर्ड को खत्म करके जो लोगों का वालंटरी कोआपरेशन मिल रहा था उसको सरकार ने बन्द कर दिया।

श्रीमान्, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ और वह यह है कि अगर हम सचमुच चाहते हैं कि हमें जन-जन का वालंटरी कोआपरेशन मिले तो जो मैंने एक योजना प्लानिंग कमीशन को भेजी थी, उसे सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिये। उस योजना में मैंने इस बात पर सरकार का ध्यान आकर्षित

किया था कि सरकार को परिश्रमालय खोलना चाहिये और हर व्यक्ति को, चाहे वह एजुकेटेड अनएम्प्लायड हो या अन-एजुकेटेड अनएम्प्लायड हो जब तक उसको नौकरी न मिले, उस परिश्रमालय में छः या आठ घंटे सूत कातने या दूसरा किसी किस्म का काम देना चाहिये और उसके बदले में उसको कम से कम भोजन दे देना चाहिये। उसमें उसको समाज सेवा की भी ट्रेनिंग दी जा सकती है। इस तरह का एक कैम्प यहां पर जरूर शुरू हुआ है लेकिन मुझे पता नहीं है कि वह किसी योजना के मातहत शुरू किया गया है या मेरी योजना से ही प्रेरणा लेकर वह "बकं रिओरियंटेशन कैम्प अंडर दी लेबर मिनिस्ट्री" शुरू किया गया है। चार पांच सौ नवयुवकों को उसमें ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन मैं यह चाहती हूँ कि ऐसे कैम्प हर शहर में खोले जायें ताकि जो नवयुवक नौकरी की तलाश में इधर उधर दफ्तरों में दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाते हैं उनको एक नई रोशनी मिल सके। तो आवश्यकता यह है कि ऐसे परिश्रमालय हर शहर और हर गांव में खोले जायें ताकि हर नवयुवक को पता चल जाय कि उसका भविष्य आशामय है। वह यह समझे कि यद्यपि उसे आज काम के बदले पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन उसको जो ट्रेनिंग मिल रही है, उसके कारण उसका सुन्दर भविष्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि आनरेबल प्लानिंग मिनिस्टर साहब मेरी इस दरखास्त पर जरूर ध्यान दें। जो योजना मैंने भेजी थी वह फाइलों में किसी बंडल के नीचे दबी पड़ी होगी, लेकिन मुझे आशा है कि वे उसे निकलवा कर जरूर उस पर और करेंगे। आज हमारे नवयुवक अनएम्प्लायड होकर रिएक्शनरी फोर्स के हाथ में पड़ जाते हैं, हुड़दंगा भ्रमाने वाले लोगों के हाथ में पड़ जाते हैं, ऐसी पार्टियों के हाथ में पड़ जाते हैं जो कि उन्हें बरगला कर यूसलेस सिटिजन बना देती हैं, उनके जीवन को बिलकुल निष्क्रिय बना

देती हैं। इससे अच्छा यह होगा कि ये हमारे देश के भावी नेता अच्छी तरह की ट्रेनिंग लें, अच्छे सम्पर्क में रहें जिससे उनको अच्छे विचार मिलें और साथ ही साथ एक नयी आशा की रोशनी का उनके जीवन में उदय हो। धन्यवाद।

श्री ए० बी० कुम्हम्बु (केरल) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूँ लेकिन वालंटरी, एफर्ट डेवल कहने में कोई फायदा नहीं मिलेगा। जिन लोगों को वालंटरी एफर्ट करना हो, उनको कुछ मिलना भी चाहिये। हम इस मुल्क में कई तरह की कमेटियाँ आर्गनाइज करते रहते हैं, लेकिन उनका काम आफिशल हो करने रहते हैं। मेरा कहना यह है कि गवर्नमेंट आफिशल्स का कंसेप्शन पूरी तरह बदलना चाहिये।

जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक कभी वालंटरी एफर्ट नहीं होगा। मैं सिचाई के बारे में ही एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे यहां हर एक गांव में कई तालाब हैं, कुयें हैं और उनमें से कीचड़ और मिट्टी निकाल देने से अच्छी तरह से पानी मिल सकता है और इस पानी से सिचाई हो सकती है। लेकिन हमारे इंजीनियरों से पूछो तो वे कहेंगे कि इंजीनियरिंग के काम में इसको सिचाई नहीं कहते हैं। सिचाई को मंस्कृत में कहते हैं "जलसेचन"। जल से पानी सींचन की क्रिया को जलसेचन कहते हैं। यह काम तालाब से भी लिया जा सकता है, कुयें से भी लिया जा सकता है। फिर भी हमारे इंजीनियर लोग इस तरह की सिचाई को सिचाई नहीं मानते।

केरल में हमने हर एक जिले में कमेटी आर्गनाइज की हुई है। हर-एक महीने में उसका सम्मेलन होता है और तरह तरह के काम वह करती है। ये कमेटियाँ सोशल प्रोग्राम बनाती रहती हैं और अस्पताल भी

कायम करती हैं। मैं अपने यहां के एक एक गांव का उदाहरण दूँ कि वहां केवल ६०० आदमी रहते हैं। लेकिन उन्होंने २५ हजार रुपया कमा कर उसको एक बड़ी इमारत बनाने में खर्च कर दिया। उसके बाद यह इमारत अभी हाल ही में केरल गवर्नमेंट को सौंप दी है। इसी तरह से १०००० ६० खर्च करके एक इमारत बनाई—उसका नाम गांधी मंडप है—वह भी अभी केरल गवर्नमेंट को सौंप दी गई। इसी तरह और गांवों में कोओपरेशन और मिहनत से काम होता है। तो भी गवर्नमेंट आफिशियल्स के बतवि और उनका कंसेप्शन के कारण इन मेहनत करने वाले लोगों को आगे बढ़ने की आशा नहीं होती। मैं कहता हूँ कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना चलाने के कार्य में विजय पाने के लिये पब्लिक कोओपरेशन और वालंटरी एफर्ट की बहुत जरूरत है। यह भी सोचने की बात है कि जनता किस तरह से कोओपरेट करे? इस मुल्क में ७५ परसेंट तो हमारे किसान लोग हैं। यहां करीब १३ करोड़ एकड़ जमीन ऐसी है जो निकम्मी पड़ी रहती है और इसको किसानों को देने के लिये कोई कोशिश नहीं करता, कोई हिम्मत नहीं करता। अगर यह १३ करोड़ एकड़ जमीन किसानों को खेती के लिये मिल जाती तो वे कुछ कच्चे भी, हमसे भी सहयोग करते और खेती की उपज भी बढ़ाते। हमारी खाद्य स्थिति बहुत सुभीबत में है और इसलिये भी हमें ऐसा करने की जरूरत है। मैं कहता हूँ कि वालंटरी एफर्ट सिर्फ कहने से ही कोई फायदा नहीं, इसको अमल में लाना चाहिये। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर विजय न पा सके तो हमारे मुल्क को बहुत तकनीकों का सामना करना पड़ेगा और यह बहुत ही रंज की बात होगी। तो विजय पाने के लिये हमें काम भी चलाने चाहियें, लेकिन वह तो कभी होगा नहीं। मैं कहता हूँ हमारे देश के लोगों के लिये योजना की जानकारी कराने के लिये एजुकेशन जरूर होनी चाहिये। हमारे मुल्क में चारों

[श्री ए० बी० कुन्हुम्बु]

और सेमीनार हो रहे हैं जिनमें दूसरी पंचवर्षीय योजना की सभी बातों के बारे में पढ़ना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं और उम्मीद है कि उसमें सभी लोग शामिल होंगे।

केरल के बारे में कहने वक्त मुझे एक बात और कहनी चाहिये। हमारे माननीय सदस्य पारिल जी ने कहा वहां कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अभी हकूमत कर रही है और वह इंडिविजुअल लिबर्टी सप्रेस करेगी। मैं कहता हूं कि खुले दिल से वे केरल में जाकर सभी कामों को देखें कि वहां क्या हो रहा है और कम्युनिस्ट हकूमत को अंधी आंखों से न देखें। मैं कहता हूं कि यदि वे खुले दिल से देखेंगे तो उनको अपना खयाल बदलना पड़ेगा। वहां की कम्युनिस्ट सरकार इंडिविजुअल लिबर्टी को सप्रेस नहीं करती। और दूसरे देशों के बारे में मैं नहीं सोचता, मैं अपने देश में बैठता हूं। मैं अपने देश के बारे में बातचीत करता हूं और फिर केरल में जो कम्युनिस्ट सरकार कायम हुई है वह तो हमारे कांस्टिट्यूशन के मुताबिक, उसके अनुसार ही कायम हुई है। वहां कैसे कोई इंडिविजुअल लिबर्टी को सप्रेस करेगा?

श्री असौद सिंह बिष्ट : वह तो कांस्टीट्यूशन का फंडामेंटल राइट है।

श्री ए० बी० कुन्हुम्बु : ठीक है। तो भी केरल के बारे में और कम्युनिज्म के बारे में इस तरह से कहने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन ये लोग पिछले जमाने की बातों को जरूर कहेंगे और आजकल की स्थिति इंटरनेशनल स्थिति को नहीं देखेंगे। वे अंधी आंखों से कम्युनिस्ट सरकार को देखते हैं। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता। तो इस प्रस्ताव में हमारे सदस्य महोदय ने जो कुछ मंशन किया है वह बहुत ठीक है। मैं चाहता था कि गवर्नमेंट आफिसर को सब तरह से अपना आउटलुक चेंज करने का भी इसमें जोर होता। हम अपनी पब्लिक

को साथ ले कर उसकी सहायता में भाग बढ़ सकते हैं।

हमने अपने यहां हर एक ब्लाक में ब्लाक एड्वाइजरी कमेटी आर्गनाइज की है। मेरा सजेशन यह है कि पंचायत बोर्डों को अपने इलाके के अन्दर जो जो भी इरीगेशन या और तरह के प्रोजेक्ट करने हों उनको पूरा करने का अधिकार सौंप देना चाहिये। हमें पंचायत बोर्डों को अपने विश्वास में लेना है और उनके जरिये ही अपने सारे प्लान तैयार करने और उन्हें पूरा कराने का काम कराना चाहिये। उन कामों को करने के लिये उन्हें मिहनताना के तौर पर कुछ पैसा देना होगा ताकि वे ज्यादा ईमानदारी से अपना काम कर सकें।

(Time bell rings.)

श्री कृष्ण मोहन प्यारे सिंह (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव आज सदन के सामने है, उसका उद्देश्य, उसकी शब्दावली ऐसी है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि शुबहा और संदेह की गुंजायश नहीं है। मैं यह मानता हूं कि यह प्रस्ताव अधिकारपूर्ण नहीं है और न कोई पेनेसिया है जिससे हमारे सभी दुख दर्द दूर किये जा सकें। योजना के इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये हमारे माननीय प्रधान मंत्री और उनके दूसरे साथी मंत्री बार बार लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, समझाते रहते हैं कि यह सारी योजना तब ही सफल होगी जब देश का जन-सहयोग प्राप्त होगा। इस प्रस्ताव के जरिये जन सहयोग की ही याचना की गई है। इस प्रस्ताव को पास कर देने से यह याचना पूरी हो जायेगी और गिरा देने से जो दूसरे विचार के लोग हैं, उनकी भाषा पूरी हो जायेगी। मैं दोनों बातों में से किसी को नहीं मानता हूं। पर मैं ऐसा समझता हूं कि समय समय पर ऐसे प्रस्ताव के जरिये इस महत्वपूर्ण सदन में जहां देश के चने हुये लोगों के जरिये चुने हुये सदस्य भेजे गये हैं,

उनके भीतर विचार विमर्श हो, नवादला-ए-ख्यालात हो, तो इससे लाभ होने के बदले किसी तरह की हानि हो, ऐसा मुझको नहीं दीखता है। मैं समझता हूँ कि हम सबों को माननीय सम्मेलना साहब के इस प्रस्ताव के लिये जिसे माननीय मल्कानी साहब ने हमारे सामने रखा है, आभारी होना चाहिये और इसकी निन्दा नहीं करनी चाहिये। इतनी देर में हमने एक दूसरे के विचारों को मनन का अवसर प्राप्त किया और उससे मुझे लगता है कि कुछ लाभ अवश्य होना चाहिये। इस अवसर पर मैं भी उचित समझता हूँ कि मुझको सामुदायिक विकास योजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों के क्षेत्रों में जो कुछ काम करने तथा देखने का अवसर मिला है, उसका कुछ अपना तजुर्वा में मदद के अपने माननीय सदस्यों के समक्ष और आपस में सामने रख दूँ।

मैंने विकास खंडों में और सामुदायिक विकास क्षेत्रों में अच्छे में अच्छा काम होने देखा है और मुझे यह भी देखने का अवसर मिला है कि कहीं कहीं केवल कागजों के ऊपर ही टागैट पर पहुँचने की चर्चा होती है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि काम वहाँ अच्छा हो सका है जहाँ के विकास अफसर और कार्यकर्ता विकास माइनडेड हैं। साथ ही साथ जहाँ सरकारी कर्मचारी ऐसे रहते हैं जो अपने को देहात वालों से घुला-मिला लेते हैं, सम्पर्क और अपनापन स्थापित कर लेते हैं, वहाँ काम अधिक अच्छा हो सका है। साथ ही साथ मेरा तजुर्वा यह है कि जिन क्षेत्रों में बहुत सीधे-साधे लोग रहते हैं—बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुझे दौरा करने का अवसर मिला उड़ीसा में चार दिन तक सेमिनार भी मैंने देखा—जहाँ हमारे अपढ़ आदिवासी बन्धु रहते हैं, वहाँ काम करने में लोगों की अधिक सफलता मिल सकी है। अगर कार्यकर्ता उत्साही मिल जाते हैं तो उनके दिल में उत्साह और लगन पैदा कर देते हैं। ऐसे कार्यकर्ता उनकी तहजीब का ख्याल रखते हैं, उनके कल्चर

को अपने मस्तिष्क में रखते हैं। उनके गाने, बजाने, नाच आदि सब को प्रोत्साहन देते हैं। उनके हृदय को वे छूने की चेष्टा करते हैं जिसमें उन्हें खूब अच्छी सफलता मिलती है। किसी किसी स्थान में मैंने देखा कि लोग वहाँ के विकास कार्यकर्ताओं की भूरि-भूरि प्रशंसा करते पाये गये हैं। हाँ, ऐसा मैं देखता हूँ कि जो तथाकथित एडवान्स लोग कहे जाते हैं, जो अच्छे पढ़े-लिखे लोग हैं, जिनमें तमाम कामों में टीका-टिप्पणी करने की आदत होती है, उनके कारण काम कम हो पाता है। जरूरत इस बात की अवश्य है कि हम इस बात के कायल हों कि काम करने वाला जो परसोनल चुना जाय, वह सिर्फ इस मतलब से न चुना जाय कि बेकारी की समस्या हल हो रही है, एक ग्रेजुएट को इम्प्लायमेंट मिल रहा है। लोग इस मतलब से चुने जाय, उसकी परख इस कसौटी पर हो कि वे देहात के लोगों के साथ घुल-मिल कर काम कर सकेंगे यानी उनके भावों का स्पष्ट अध्ययन कर सकेंगे, उनके दिलों को छु सकेंगे। साथ ही साथ जो अफसर विकास क्षेत्रों में काम करते हैं, वे सचमुच लगनशील व्यक्ति होने चाहियें। ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। उनकी पदोन्नति होनी चाहिये। ऐसा न हो कि एक आदमी मेहनत से काम कर रहा है और जब पदोन्नति का वक्त आये तो सिविल लिस्ट उठा कर यह देखा जाय कि उसका स्थान कितनी दूरी पर है। मैंने अपनी आंखों से इस तरह के केसेज देखे हैं। मैं यहाँ पर उस अफसर के बारे में कुछ अधिक कहना नहीं चाहता हूँ और न उसका नाम लेना यहाँ पर उचित है। उस व्यक्ति को जिस जिस विकास श्रेण में भेजा गया वहाँ उसने एन० ई० एस० ब्लाक की तरक्की करके उसे डेवलपमेंट ब्लाक में बदलवा दिया। यह काम उसने केवल अपने परिश्रम से ही पूरा किया। हमारे यहाँ एक बड़ा कड़ा कमिश्नर था जो आसानी से किसी के सम्बन्ध में रिपोर्ट लिखना नहीं जानता था, लेकिन उसने भी

[श्री कृष्ण मोहन प्यारै सिंह]

उसके बारे में यह लिखा कि : "The officer deserves accelerated promotion." फिर भी प्रमोशन के वक्त उसी सिविल लिस्ट की चर्चा हुई और यह कहा गया कि उसका नाम बहुत पीछे है, इसलिए उसका प्रमोशन नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि ऐसा होने से परिश्रम करने वाले लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलता है और उनकी लगनशीलता में वृद्धि होने के बदले कुछ कमी आती है। मैंने यह भी देखा है कि जो सरकारी कर्मचारी विकास क्षेत्र में काम करते हैं और जो नानआफिशियल कार्यकर्ता उस इलाके में होते हैं, वहाँ उन दोनों में पारस्परिक सहयोग की भावना रही है, वहाँ काम कुछ अधिक हो पाया है और जहाँ एक दूसरे के प्रति खिचाव रहा है और जहाँ नानआफिशियल उसमें काम करने वाले आफिशियल को उसी दृष्टि से देखने रहे हैं जिस दृष्टि से वे पहले देखे जाते थे, वहाँ काम कम हो पाया है। मैं समझता हूँ कि चाहे फ्रैशनेबल लेडीज हों, या फ्रैशनेबल पुरुष हों, फ्रैशन से कुछ विगड़ता नहीं है। अगर किसी फ्रैशनेबल सोशल वर्कर में काम करने का माहुरा है तो वह काम करके अवश्य दिखला सकता है। लेकिन अगर उसके बदले आपने किसी भौदू स्त्री को ले लिया और कहा कि यह बड़ी सीधी सादी औरत है, खादी पहनती है, गांव की बोली बोलती है पर वह जाकर इस लायक भी न साबित हो सकी कि वह स्थितियों को योजना समझा सके तो उसका सीधापन, उसकी सादगी हमारे किस काम आयेगी।

मैंने जैसा शुरू में आपसे कहा, मैं फिर उसको दोहराता हूँ कि इसमें काम करने वाले पुरुष या काम करने वाली स्त्रियाँ जो भी हों, उनके चुनाव के समय एक ही बात का विचार होना चाहिये कि वे योजना माइनडेड हैं या नहीं, योजना ने उनके हृदय को स्पर्श किया है या नहीं। उनमें योजना को अण्वाने का माहुरा है या नहीं। मैं समझता हूँ कि साधारण बातचीत से, एक साधारण से इंटरव्यू से,

अगर हम जानने की चेष्टा करें तो ऐसी बातें मालूम की जा सकती हैं। जो सब-डिप्टी कलेक्टर नियुक्त किये जाते हैं अगर उनमें से कुछ लोगों को बर्बर यह जाने दी० डी० ओ० या डेवलपमेंट आफिसर बनाया जाता है कि वे उससे दिलचस्पी रखते हैं या नहीं, तो उसमें हमको सफलता नहीं मिलेगी। आपका जो अप्वाइंटमेंट का डंग है, वही रहे, लेकिन जो सब-डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर मिलेक्ट हो जायें, उनमें से आप जिनको उस काम में लगाना चाहें, उनके विचारों को जान कर, उनकी भाव भंगिमा को समझ कर कि उनके दिमाग में कोई आदर्श है या नहीं, उनका चुनाव करें। जिसको आप सामुदायिक विकास योजना में और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड के क्षेत्रों में काम करने के लिये भेजेंगे, अगर वे लगनशील व्यक्ति होंगे तो वे कुछ अर्थ में उस काम को अच्छी तरह करने लगेंगे।

श्री पा० ना० राजभोज : जो आदर्श काम करने वाले हैं, उनके खिलाफ हमने नहीं बोला है।

श्री कृष्ण मोहन प्यारै सिंह : मैंने बराबर उन बातों की चेष्टा की है कि मैं किसी माननीय सदस्य के वक्तव्य का खंडन न करूँ, इसलिए मुझ पर सख्त डंग का आरोप लगाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। मैंने देखा है कि एक जो आदर्शी ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने स्वास्थ्य का परवाह न करके और गांव वालों की भावना को समझ कर और उनकी इज्जत करके अधिक से अधिक काम किया है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो पढ़े लिखे गांववाले मार्गनाइजर हैं और एम० ए०, बी० ए० और न जाने क्या क्या हैं, लेकिन अगर उनमें काम करने का माहुरा नहीं है तो उनकी योग्यता और उनकी डिग्री किसी काम की भी नहीं प्रमाणित हो पायी है।

इन शब्दों के साथ मैं फिर भी आचार्य मन्कानी जी को यह प्रस्ताव

हमारे सामने रख कर हमको यह अवसर दिया है कि जिस गंग से गांवों में काम हो रहा है और गांव गांव में जो काम करने वाले आदमी बिखरे हुये हैं उनको जमा हुआ है और साथ ही साथ उनमें जो खामियां हैं, और उनमें जो सुधार की आवश्यकता है, उनके प्रति सदस्यगण प्लानिंग मंत्री महोदय के सामने अपने भाव प्रकट कर सकें, उसके लिये बधाई देते हुये बैठता हूं।

धन्यवाद।

SHRI V. PRASAD RAO (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, I cannot subscribe to the scepticism expressed by some of the friends here and perhaps, the hon. Deputy Minister also might be thinking on those lines, that a Resolution of this sort will not be of much use, since it is vague, since it does not give any specific answer to the problem of eliciting the people's co-operation. I do not think that this Resolution will not be of use. If only to focus the attention on the necessity of enlisting the co-operation of people, if only to focus the attention of those bureaucrats who are in that state of stupor, who are in that state of elevation that these people are nothing and that they could carry on everything, if this Resolution is able to move such people, I think this will have more than served its purpose. So, Sir, I am not going to subscribe to the view that this Resolution by being discussed here will be useless.

I am not going into those factors, rather those basic policies, that are pursued by the Government, which are hampering the full measure of co-operation from the people. Take, for instance, the policy of taxation which, of course, unduly puts the weight of this development on the common man rather than on the richer classes. Of course, I am not going to give a dissertation over the taxation policies of the Government nor on those policies which do more favour to the bureaucrats or the landlords. I am not, on this occasion, going to pass a detailed criticism on those policies, but I shall refer only to those

acts or things which are for the progress of all sections of the people. If such programmes are agreed to almost unanimously by all parties and by all sections of the people, why are we failing to elicit their co-operation even on such programmes and why has the Government failed to enlist the co-operation of all sections of the population? It is only on those things that I am going to dwell.

SHRI SONUSING DHANSING PATIL (Bombay): Question.

SHRI V. PRASAD RAO: Friends might question, of course. But they cannot question facts. They cannot question the practice. If the speeches that have been made here are any indication, it has become very clear that all the co-operation that could be got from the people is not being got. My friend may question from the other side, but facts remain as facts. Perhaps, if my friend had gone to the country-side and seen how much enthusiasm there is for some of the projects, for some of the Community Development projects, he could not have questioned like this; he could not have parried like this.

Anyway, take the question of Community Development where there is a lot of scope for eliciting the co-operation of the people. How much co-operation is being taken? I need not go very far to quote from the opposition sources, but the hon. Deputy Minister of Planning can go into the Community Projects evaluation reports. They themselves say that proper co-operation from the people is not forthcoming. Of course, the Minister might say, "What can we do? We have constituted committees. We have sought the people's co-operation in preparing such a big book as the Second Five-Year Plan. We are sending instructions, of course, to get all the parties' representatives and other people into these committees, and wherever it is possible, we are trying our best to get that co-operation. If people are not forthcoming, what are we to do? Do you mean to say that for everything

[Shri V. Prasad Rao.] the Government is to blame? It has become the second nature of the Opposition to blame the Government for everything that is not being done." Perhaps in his whims our Deputy Minister might indulge in another peroration. But such an indulgence cannot be a substitute for a self-critical attitude which is so necessary to understand why exactly the people's co-operation is not forthcoming. Such an attitude, which, of course, the hon. Deputy Minister had displayed on a previous occasion, when we were discussing the land reforms, will not help even in future to get the co-operation of the masses that is necessary to carry our plans forward.

Sir, the first thing that I may point out as to why the necessary measure of co-operation is not forthcoming, as far as these community development projects are concerned, is this. I do not say that absolutely no co-operation is forthcoming. Certainly co-operation is forthcoming. There is no doubt about it. But the necessary amount of co-operation is not forthcoming because the necessary amount of enthusiasm is not generated among the people. If this simple thing is not understood and if this simple thing is forgotten in the midst of the verbiage of other reasons, then, of course, the basic thing cannot be understood, and even in future proper co-operation cannot be forthcoming. Suppose, for instance, there is a question of road-making. The people must be made to feel that their future is at stake and that it will be for their own betterment to have that development. It is only by making them realise and understand that it is necessary for their future progress in life that that particular road is necessary that we can get their whole-hearted co-operation. But unfortunately the administrative machinery which we have inherited from the Britishers is not the one that can very easily respond to the needs of our people or can get the necessary enthusiasm on the part of our people and their whole-hearted co-operation. Every one of us, Sir,

understands perfectly well that the administrative machinery which we have inherited is not possibly the best-suited in the present age of development, in the present age of our welfare State, in the present age of getting the maximum co-operation from the people. In that case, taking into consideration the inadequacy of our administrative machinery and the prevalence of bureaucracy, it is the duty of the Government to see that people are associated with all phases of development and people are associated with such works. But association of our people does not mean cramming these committees with the people of their own faction and with the people of their own clique inside the Congress itself. I too have got the experience of these committees. I do not say that no committees are there in existence. In my own erstwhile State of Hyderabad or in the present State of Andhra Pradesh, of course, these block advisory committees have been formed, taluk development committees have been formed, district development committees have been formed. But may I know, Sir, by whom are these committees represented and who are the members of these committees? Are they representative of the people who are actually living there in that particular block or particular taluk or particular district?

SARBAR RAGHBIR SINGH PANJHA-ZARI
(Punjab): Of course.

SHRI V. PRASAD RAO: Yes, I am presently coming to what sort of representation is that. If my hon. friend who says 'of course' thinks that defeated candidates in the elections represent the people there, then, of course, it is entirely a different thing. If by that my hon. friend means that those who forfeited the confidence of the people represent the people, of course, then they do represent, according to that concept, the people in that area. But if my hon. friend, the Deputy Planning Minister, goes into the thousands of complaints that are there in the erstwhile Hyderabad State from his own Congress organisation,

1851 *Resolution re:*
mobilising public

[6 DEC. 1957] *enthusiasm and support* 1852
for 2nd Five Year Plan

he will find that there were several complaints about the formation of those very committees. And he himself can understand how partially these committees were formed. Even the Bharat Sewak Samaj was made a pawn in the factional game inside the Congress itself. So, Sir, it may be very easy to say that people's co-operation is necessary and committees are there; these committees that are there, of course, might have genuinely been intended for the co-operation of the people, but actually they are being used to serve the interests of not even the Congress but of particular people inside the Congress in the name of people's co-operation. And naturally, if such things are going on, you cannot expect the people to come with open hands and co-operate with you. And then, Sir, if the block development officer or the block head goes into the village and stays with some local landlord there, he does not expect the co-operation of the agricultural labour who are naturally sceptical about the *bona fides* of the landlord for the development of the village. You do not expect ordinary agricultural labour to give its whole-hearted support to a block development officer or to such development officers who are apparently supporting those landlords. So also in the matter of co-operatives, you may be thinking that proper interest is not being taken by the masses. If 70 to 80 per cent, of the loans are going into the hands of those landlords, you cannot expect co-operation from any other sections of the peasantry. If co-operative societies are used as tools in the interest of usurpers in the village, you cannot expect co-operation from the other sections of the peasantry, and that is but natural. Unless these things are mended, there is no use saying that no co-operation is forthcoming from the masses. In this connection, Sir, I am reminded of the criticism made by my hon. friend who is not here, Mr. Chandulal Parikh. I know that he is very much allergic to communists. But I do not blame him for that because he represents that class which is very much allergic to communists. Now,

Sir, he alleged that under communism, under the powerful rule of the Communist Party, individual liberty is suppressed. I will tell him only one thing. Let him compare the present regime in Kerala where communists are in power with the previous 10* years' regime of the Congress inside Kerala, when section 144 was imposed and when no meetings were allowed for several years in Trivandrum. It is the Communist Government, it is the Communist Ministry that has for the first time lifted the ban on the meetings in Trivandrum. Does it mean that individual liberty and the individual freedom is suppressed by the Communist Party or by the Congress? It is for the first time that the Kerala Communist Ministry has invited friends from his own class, from the capitalist class, to frankly come and discuss matters that are to be adopted by the Kerala Ministry for the future development of Kerala. Does he mean to say that it is suppressing the individual liberty or individual freedom? If he means by individual freedom the freedom for the capitalists to suppress the working class with the help of the police, then certainly Kerala is not the place for him to choose. But if he means by that the development of industries with the public co-operation and with the help of the Government, then certainly, and with open arms, the Kerala Communist Ministry is inviting all the capitalists throughout India to come and invest there with the assurance that the Kerala Ministry is there to help and defend all the legitimate interests of the industrialists. So no importance need be attached to the insinuations that are levelled against the communists or the Communist party.

SHRI T. J. M. WILSON (Andhra Pradesh):
May I interrupt?

SHRI V. PRASAD RAO: I am sorry I have no time. Otherwise, I would have welcomed interruptions. In fact, I would have been glad if you had given me a few more minutes and I would have certainly answered all

1853 *Resolution re:* [RAJYA SABHA]
mobilising public

[Shri V. Prasad Rao.] interruptions in that case; there is no doubt.

Coming to the question of co-operation, my friends might ask "What has your Government done? What has your Ministry done in Kerala to elicit co-operation?" May I remind those friends, of course many may be knowing but still may be pretending not to know it, and I may say for their benefit too, that immediately on the assumption of the Ministry, the Kerala Government did at every level have popular Committees with representatives of all sections of the people, including the Congress, not excluding any Party, unlike their practice in other States. For instance, in my own district, there are Block Advisory Committees where the communists had polled 80 per cent, of votes but still you don't find a single communist represented in that Committee. Such sort of practice has never been followed in Kerala but there every effort has been made, of course, to elicit the cooperation of other parties. Unfortunately, there today the Congress is mobilising the people not for any constructive programme, not for anything else but to invite repression. That is the method they are adopting and they say that at other places they are not able to get cooperation. Where you follow the right method or the right approach, certainly you can get the cooperation of the people but today by these wrong methods, by relying on landlords and capitalists, if you say that you are not getting that measure of cooperation which you should get, it is natural and it is inevitable. So besides formulating a correct policy, you must have a correct approach also to this matter. You must have faith in the masses so that you could mobilise the people.

I will cite one more example. You know Pandit Sundarlal who was a follower of Gandhiji. He had been to China and he said that half a million people could be gathered for the construction of Hoi river project and about which our own delegation

enthusiasm and support 1854
for 2nd Five Year Plan

had testified that such a gigantic project could be built in 80 days because of the cooperation of the people. It is high time we ponder why such cooperation is forthcoming there and not here. It is no use saying that it is because of the totalitarian Government or that this project could be built because the Government there compelled all the peasants and the masses to do so. Perhaps a totalitarian Government could get at the masses but they cannot make heroes of the people. A totalitarian Government, a dictatorship could never do that. It is only a Government that fulfilled the aspiration of the people that could do such things. So it is high time that our Government should analyse such things and see why such a cooperation is not forthcoming here. Certainly if China could do it, we can do it. I am fully confident that Indians could do it. I fully believe that we want to develop and if you want cooperation, you can get it provided the right approach is there. I, on behalf of my party, say that we are fully prepared to cooperate provided the Government is also prepared to cooperate.

THE DEPUTY MINISTER OF PLANNING (SHRI S. N. MISHRA) : Mr. Vice-Chairman, it has been my privilege during this fortnight to attend to two Resolutions—I may say very important Resolutions—in this House, one following very closely the other. We are thankful to the hon. Members for exercising their minds on this very vital subject of public cooperation which I must mention is next to our heart as it must be to theirs. But it is my regret that so many points have been raised during the course of the discussion, ranging from family planning to anything that you can conceive of under the sun, that even if I move with a Sputnik speed, it would be difficult to keep pace with them.

I have listened to the debate with great interest and respect but I must confess that my hope and

1855 *Resolution re:
mobilising public*

[6 DEC. 1957] *enthusiasm and support
for 2nd Five Year Plan*

desire to be benefited by it has not been fulfilled. The tone was set by the hon. Mover of the Resolution, and along with him a number of other friends seemed to give me an impression as if they had retired to the Himalayas during the last five years of very vital developments in India. I would also mention this in this particular field of public cooperation. There is no doubt that it would do well if the hon. Members should always keep this subject under their review because they are very close to the people. But I am sorry to find that the debate on this Resolution has been sought to be converted into a general debate on the Plan—the Plan, its structure and philosophy; the Community Development Projects, their structure and philosophy; the dichotomy between public and private enterprises and things of that kind. For many things raised, I may submit that the proper time for taking them up would come when the Budget Debate commences or earlier when this House takes up, if there is such a motion as the consideration of the working of the Second Plan. So [I would not like to throw any light on many of the points which have been raised. And if hon. Members feel somewhat disappointed, I can only say that I am helpless in view of not very strict relevance of those points to the discussion this afternoon.

Before I begin to take up some of the important points, I would like to thank my hon. friend Shri Algu Rai Shastri for his very emphatic and eloquent speech opposing this motion. I know that there are very few persons who can equal him in his eloquence and the effectiveness of the language which he has used.

After having said that, I would like to say at the very outset that we consider that public cooperation is the very breath of democratic planning and particularly in an under-developed country. It is my firm opinion that in an under-developed country we have not only to build an economy

but to build a nation. I would like to explain this , at some length. Without public cooperation you may build capital, you may even achieve the targets that you have laid down in the Plan but you would not be able to build the human beings. Those very targets that you achieve may lack the very vital throbbings of life, they may be dead targets, they may not be the symbols of life. So it is the considered opinion of the Government as it is no doubt of the hon. Members that we must do everything to secure public cooperation. But when the hon. Members were all the time directing their attention to the Government in this respect, I was feeling a little surprised because as representatives of the people, hon. Members should have brought some fresh experience and also told the House what they have been doing particularly in this field.

4 P.M.

We have here about 750 representatives of the people, not in this House only, but in both the Houses together. And we have about 4,000 representatives all over India, functioning in the legislatures. Sir, we have the Members of Parliament and those of the State legislatures functioning in the 328 District Development Committees all over the country. Members of Parliament! And members of the legislatures again are functioning in the Block Advisory Committees which would be numbering about 5,000 throughout the country at the end of the Plan. These are very important and vital bodies in which the hon. Members have the scope for thinking out ways and means of securing public cooperation. But they have not said anything concrete as to what have been their experiences while working in these very important bodies. Sir, when I hear them saying that Government is doing or not doing something, in this field, I am reminded of what Bernard Shaw said in this Preface to the Apple Cart—"So you see, I cannot be a Christian except through the Gov-

1857 Resolution re:
mobilising public

[RAJYA SABHA] enthusiasm and support 1858
for 2nd Five Year Plan

[Shri S. N. Mishra.] ernment's action." This seems to be the mentality which is gripping hon. Members. They are always thinking -of the Government while they are thinking of public cooperation. It is quite clear, Sir, that any government would fall short of the requirements of the situation. Any Government is bound to prove small in relation to the great needs of the situation. Any party, be it the party to which I have the honour to belong, is bound to fall short of the requirements of the situation. So the whole nation has to gear itself up to the task.

Sir, some hon. Members at times feel somewhat sceptical and cynical about the targets which they seem to criticise as ambitious. I would like to say that if the whole nation puts forth its best, there should be absolutely no doubt that we shall not only achieve the targets, but we would be able to go much beyond them. We may not have any control over the foreign exchange resources. But the internal resources should not only be achieved but they can be multiplied manifold if all the representatives of the people put their shoulders to the wheel.

Sir, what are the important principles on which public cooperation may be expected to be achieved? some hon Members have tried to throw light on this question. ' An individual, when he feels that his interest is completely identified with the programme, can take part in the implementation of the programme. When he feels that he has some share in the forming of the decisions, then he can take part enthusiastically in, the implementation of those decisions, Now, how was this Second Five Year Plan formulated? I am not here to go into all the details connected with that. These are well known to this House. Not only the legislatures, but a large number of public bodies all over the country were consulted

during the formulation of the Second Five Year Plan. So we can say in a real sense that this is a people's plan. That being so, it is for the people's representatives to see that this people's plan is carried out by the people with all energy and enthusiasm. It is, of course, necessary for the Government to create conditions in which the public representatives and the people can put forth their best. I shall come presently to what the Government has been doing to create those conditions.

Sir, this Resolution wants to place before us, in an implied way, that nothing is being done, or that very small or scanty efforts are being made to secure public cooperation at all levels. What is exactly in the mind of the hon. Mover is not quite clear to me. Does he want committees at all levels to serve this purpose? If that is his intention, that has already been done. From the very base to the apex, we have now a continuous chain of these organisations. We have got the village panchayats which probably number about 123,000 all over the country. And then we have got, above the panchayats the Block Advisory Committees. Above them there are the District Advisory Committees and then at the State level there are the State Planning Advisory Committees. When you come to the national level, you have got the Consultative Committees of the Members of Parliament, both for Planning and for the Community Development Programme. You have got the National Advisory Committee on Public Cooperation. In the same way you have got the Bharat Sevak Samaj and other organisations working which Government has been trying actively to assist. , So in this way you have got an organisational set-up from the village panchayat up to the National Advisory Committee here. In all these committees it is the Members of Parliament and the members of the State legislatures and other leading

1859 Resolution re.
mobilising public

[6 DEC. 1957] *enthusiasm and support 1860*
for 2nd Five Year Plan

public representatives who have been functioning. Take for example these village panchayats, on which rightly on. Members have concentrated a good deal of attention. We attach a great deal of importance to the functioning of the village panchayats. Unless these small village republics function in an effective and vigorous manner, there is no salvation for the country. So we are laying a great deal of stress on these. The hon. Mover of the Resolution referred to the Balwantarai Mehta Committee Report in this connection and suggested something about democratic decentralisation. That is in fact the very core of the programme of the community development. It may be that by now we might not have succeeded to a great extent in setting up institutions, agencies and methods which might secure this end. But that is the very core of this programme. And as you must have observed during the course of discussion on this Resolution and earlier in this House, in this programme we lay a great deal of stress on the effective functioning of the village panchayats. Every village panchayat is entrusted with Rs. 2,000 which it can spend according to its programme. It is the "village panchayats that formulate the programmes which have to be implemented in their areas, and it is with their active cooperation that the programmes are implemented. It may be, Sir, that there may be a snag here and there. It may be that there are deficiencies here and there. But they require some time, and I think the hon. Members' impatience in this respect may be justifiable on the basis of limited experience. But so far as the entire country is concerned, the village panchayats are going to be very actively assisted by the community development programme.

Another point that was generally mentioned was in connection with the difficulties in government offices and the hon. the Mover of the Resolution referred to red-tapism and the complex procedures which have general-

ly been standing in the way of securing public cooperation. I very much sympathise with him and I agree to a certain extent that the procedures are complex in many cases and there are difficulties in Government offices. We are constantly giving thought to this aspect of the problem. But it has to be borne in mind that we have to create conditions in such a manner that there are no major upsets, leaving in the balance no good results. Anything that we do must not be of such a nature that there might not be the desired result. And, therefore, although we are giving very anxious thought to the reorganisation of administration and the simplification of procedures in the offices, it is sought to be done in a manner that there might not be a major upset.

Sir, I come from a State where, as you probably know, there have been some inspiring examples of public cooperation. The Mover of the Resolution was very kind enough to refer in very good words to the work being done on the Kosi Project and the Burhi Gandak Project. Sir, I am one of those who have had the privilege of working with thousands of young boys in NCC camps. I think at the time I visited the Kosi Project, about 9,000 to 10,000 boys were working on the Kosi Project. I lived with them for three days. I would never forget those three inspiring days that I lived with them

Again, Sir, in Burhi Gandak, Khion, Kamala and other embankments, you will be surprised to learn that about 550 to 600 miles of embankments had been constructed mainly with the cooperation of the village panchayats. My hon. friend over there was speaking something about Huoi Project in China which was completed with public co-operation within a very short time. Let us not slight what we have done in this country, what the people in this country have been doing. Here I give you an example that 550 to 600 miles of embankments were constructed during a short period of one

[Shri S. N. Mishra.] and a half years. Just think of it, just think of the whole length of it; probably from Delhi up to Patna, the whole distance was covered by embankment with the active cooperation of the village panchayats in that area. Particularly in the present stage of lack of education, lack of training, this whole matter assumes great significance. Similarly, Sir, in the Koji Project about which I mentioned. Not only the NCC boys worked there, not only the *shramidanis*, those people who give voluntary labour, worked there, but the Bharat Sevak Samaj organised the people on such a vast scale in labour cooperatives that it should excite the admiration of all. So, these are very important things that have been achieved with public cooperation.

Then, Sir, Prof. Thomas and some other friends mentioned something about the organisation of youth. Sir, casting a glance at me you can think how very enthusiastic I myself would be about the programme of the organisation of youth. I am associated with an organisation which has been sponsored by the Planning Commission and which is called the University Planning Forum. Some hon. members, particularly Hon. Shri Deokinandan Narayan, spoke something about the Small Savings Campaign to be carried amongst the student population. This is an idea which we have already worked and, therefore, when I say that the hon. members seem to be absolutely innocent of some of the important things that we have been doing, I am not beside the mark. By the fame, I would like to convey to the House, that the students and teachers in the Universities and the constituent colleges have been able to mobilise savings to the extent of Rs. 1,17,000. They inaugurated this programme only a few months back and they have been able to collect the amount. But the potentialities in this direction are much vaster and we are going to achieve them. This popula-

of students and teachers in the Universities and the constituent colleges is going to bring about a revolution in the thinking of the people under the auspices of the University Planning Forum. It is a very vital movement of one million University men and women all over India. At the moment we have got a population of about 8 to 9 lakhs of students in the Universities and the constituent colleges. Probably they would go up to about 1-2 millions at the end of the Second Five Year Plan. So, let us look with hope to this vital movement of the University Planning Forum, which had done a good deal towards creating planning consciousness amongst the students' population and which had done vital work and thinking in respect of the Plan. Sir, what exactly is the idea behind the Planning Forums? Not only they have to create plan-consciousness amongst the University students and teachers but also amongst the boys and girls reading in high schools and other educational institutions. So, each Planning Forum has to take under its care about half a dozen high schools. If every college forum acts up to this, there should be about 2,000 schools benefiting under this scheme. So, it means that we have a programme of igniting not only one candle, but a chain of candles—these one million boys and girls spreading plan-consciousness amongst many million boys and girls in the high schools and teachers and boys and girls going to the countryside and spreading the message of the Plan.

I do not know whether I am near-ing my time. I had 30 minutes but I think probably I have not spent more than 15 to 18 minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. B. JOSHI)
: You have already finished 22 minutes.

SHRI S. N. MISHRA: I thought it was 18 minutes. So, I am sorry.

Sir, look at the contribution made-by the people. Although it would:

not be right to evaluate in terms of money what has been done by the people during the First Five Year Plan, on a most conservative estimate the contribution of the people in terms of money, materials and labour would come up to about Rs. 20 crores or so. I am told that under the Community Development Programme the contribution made by the people up-to-date is about Rs. 46 crores or so. Having said that, I would again advise the House not to look at the contribution made by the people in terms of money so much.

Now, Dr. Gour mentioned something about the constitution of a Project Committee. Sir, it is a good and concrete suggestion which came from him but I would like to inform the House here again that we have already taken steps so that in all important irrigation projects, there should be joint committees, consisting of the representatives of the administration and the public agencies engaged in securing public co-operation. We have already written to the State Governments and soon the results would be discernible. So we have already taken steps even in this respect.

SHRI V. PRASAD RAO: May I know if there is any such committee so far as the Nagarjun Sagar Project is concerned?

SHRI S. N. MISHRA: I have said that we have recently written to the State Governments about the constitution of such joint committees and they are soon going to be formed. In fact it is our idea that with all big projects the agencies concerned with public co-operation should be associated.

Now, Sir, I would say a few words about the Sadhu Samaj, although the Government is not directly associated with it. This association has not come into being at the initiative of the Government. There seems to be a wrong impression in the minds

of the hon. members of this House that this has been, in a sense, sponsored by the Government. This is a body which has been sponsored by the Bharat Sevak Samaj and we are glad that such a body has come into existence. It is no use making oblique remarks about the Sadhus. If they want to contribute to the development programmes, we should all welcome them. Their number is very vast and the number of their followers is vaster still. So, if we can bring them within the orbit of the construction programmes, it should be all to the good of the country.

Now, a few oblique remarks were made about the ladies associated with the Social Welfare Board activities. My hon. friend, Shrimati Savitry Devi Nigam, very effectively replied to them. I can only express my own regret over the remarks made about the ladies who are doing good work under the Social Welfare Board. Sir, I do think that the hon. member who made those remarks did not mean them, although the words seem to be creating that impression.

Now, Sir, some complaints were made by my hon. friend, Shri V. Prasad Rao. He said about some of the committees being filled with partisan men. I would strongly reject any such charge. Sir, if the hon. Member were to put down something in writing, we shall certainly enquire into it but I felt he perhaps was referring to past cases. If he has something to say about the constitution of certain committees, we shall certainly look into them and find out whether the accusations are correct.

SHRI V. PRASAD RAO: Plenty of things have been sent in writing.

SHRI S. N. MISHRA: There are many other points but as I told you in the very beginning, it would be difficult for me to cover all of them. I would say in the end, Sir, as you

[Shri S. N. Mishra.] I seem to be somewhat anxious about my finishing the speech now as you have to take up the other resolution, that in view of what I have said, this resolution would appear to you as reiterating what the Government is already doing and in connection with which Government has already done a lot and proposes to do a lot. It is not only in respect of social welfare programmes to which pointed attention seems to have been drawn in the resolution but all along the line we want to mobilise public co-operation—not only on the Government level, not only through the association of the public with the Government bodies but with the active co-operation of the public representatives and members of Parliament and of State Legislatures, the village panchayats, local bodies and all the rest of it. Sir, such resolutions seem to confuse more than help us because we do not know where we stand after doing all these things. If there are some concrete suggestions, they are all very welcome to us but concrete suggestions do not seem to have issued out of this debate. That is my regret and so the debate, in a sense, has been very disappointing and confusing. My hon. friend was saying that he could anticipate my speech. He tried to anticipate what was going to be my speech and he said that I was going to characterise this debate as a waste of time. Sir, I would be the last person to do that because after all, there are many useful points which have come out during the course of the debate which should receive the active consideration of the Government.

With these words, Sir, I would request the hon Mover of the Resolution to withdraw it. But before I do that, I would like to say again from the side of the Government that so far as we are concerned, we attach the greatest importance to securing public co-operation. I am reminded in this context of a Chinese saying. Probably this would please the hon.

Members on the other side. The Chinese saying is that when the whole people sigh there is a storm and when the whole people bang their feet, there is an earthquake. Sir, with the whole people behind the Plan, there would be a real revolution which would transform society and transform people, their habits and their ways of thinking and I would invite the co-operation of all hon. Members in this direction.

Thank you.

SHRI N. R. MALKANI: Sir, my work has been made, to my mind, very light by the hon. Minister. Whatever he said was almost supporting what I said, with a little slant this side, with a slight tilt that side but in substance, I think, he sympathised almost with what I said. He said we are in need of public co-operation. We are in need of it; we all agree that public co-operation is necessary for the success of the Plan. We are all anxious to have it. The Reports say so; your Project Evaluation Report says so; your Vice-Chairman of the Planning Commission says so; the other day Dhebar Bhai said so. We have all said so with strength and great vehemence but, as far as public co-operation is concerned, it is not forthcoming as it should be. There is not that public enthusiasm which we desire or we want. The question is how to get it. My point is that these are the ways of getting it and I thought I had tried to give what are called concrete suggestions. It was not a vague thing. Everything that I mentioned was drawn from my experience. As a matter of fact, I drew on my experience fairly generously, experiences in Kashmir, Gujrat, Delhi, Bihar and so on. I would again reiterate that whatever I said was not theory. The hon. Minister knows very well that I speak from experience and all that I wanted was that what has been taken in hand should be pursued with the will, with the vigour, with the strength which I have not so far perceived. Perhaps that is the only difference between us. We want public co-operation; we do not see

public enthusiasm and we want to arouse public enthusiasm. I suggest this method and you suggest the very same method. We have just made a start but we have to make a very good start and give it a good push. I hope we will give it a good push. I do not want to press this Resolution for the reason I do not want to confuse either the Deputy Minister or the public or the Members of this House. If the Resolution confuses their mind, I would rather withdraw it. I do believe that the first Plan had a substantial success and I have been saying always that the first Plan had a substantial success. The second Plan is a good improved Plan; it is a plan for the people. I would not say that it is the people's plan. I wish it could be called the people's plan. It could be made the people's plan hereafter but today it is not the people's plan to my mind. At the same time, I do believe Government wants public co-operation and is anxious to have it. Before I withdraw the Resolution, I want to say to my friends here, Members of Parliament or of Legislatures in the States, that this is as much our duty as the duty of the Government. We get the Government we deserve and we deserve a better administration, a better policy, a more successful plan. We want the Government to be as responsible as we ourselves are. We cannot say we offer co-operation but it is not taken advantage of and in such a case we should not offer it. I am sorry to say that very few of us offer that co-operation which really sometimes Government solicits, at least the Community Projects Administration solicits and which it is not getting, I must say. The general public looks to us and we in turn look to the Government. It is a wrong and vicious circle. I would like to break that circle and say, not only Government, not only the administration but, in a sense, more than all that, we, Members ourselves who are in close contact with the public should say that our co-operation is forthcoming and that this in turn will lead to public enthusiasm.

Sir, I do not wish to press this Resolution at all because there is not

much of a difference between the Minister's point of view and my point of view.

*The Resolution was, by leave, withdrawn.

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTION REGARDING BAN ON THE EXPORT OF MONKEYS

SHRIMATI RUKMINI DEVI ARUN-DALE
(Nominated): Sir, I move:

"This House is of opinion that Government should ban forthwith the export of monkeys from India."

I am afraid, Sir, it is hardly worth while going through with this Resolution as there is really very little chance to put the case before the House or to get a reply from the Minister. Still I shall introduce the subject because I feel this is a vital question; it is something which affects the people of India as a whole and, since it is not possible for everyone to vote freely, as it is a moral issue, if it is at least possible for everyone to speak freely, I personally don't mind whether it is put to the vote or not.

It seems a strange thing that in this country it is so difficult to convince people on this particular question, a country which has for so long spoken about compassion and *ahimsa*. I cannot understand how there could be differences of opinion in regard to this export of monkeys when there is no doubt about the cruelty involved in it. First of all it brings tremendous suffering to millions of very sensitive creatures. We have no right to cause them so much suffering. They are supposed to be next to human beings in sensitiveness, and that is the reason why they are so much wanted by the laboratories. When they are so sensitive, it seems very strange that we are so insensitive to what they feel.

♦For text of the Resolution, *vide* col. 176P tapra.